

[2023] 8 एस. सी. आर 243

हसमुखलाल माधव पटेल और ए. एन. आर.

वी.

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 8194)

15 जून, 2023

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956-एस। 2 (32) , 81 , 81 (1ए), 81 (3), 397,398

कम्पनी अधिनियम, 1913-एस। 105 - सी-पहला उत्तरदाता एक निजी है

1 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी वाली सीमित कंपनी-तीन समूह हैं अर्थात एच. एम. पी., एस. और वी. पी. पी.-अपीलार्थी संख्या। 1 और 'एच. एम. पी.' समूह के रूप में वर्णित 2 के पास चुकता शेयर पूंजी 'एस' समूह का 30.80% था जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या द्वारा किया गया था। 4 & 5 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और 'वी. पी. पी.' समूह का प्रतिनिधित्व उत्तरदाता संख्या द्वारा किया गया था। 2 & 3 भुगतान पूंजी में 24.20 प्रतिशत था-के जवाब में

अपीलार्थियों द्वारा दिए गए सावधि ऋण के प्रस्ताव पर, बैंक ने उन्हें न्यूनतम रुपये के लिए शेयर पूंजी बढ़ाने की सलाह दी। 2 करोड़-प्रथम उत्तरदाता कंपनी अपने निदेशकों को एक नोटिस भेजती है, जिनकी संख्या चार है। , अपीलार्थी और उत्तरदाता 2 और 3-बैठक 18.12.2009 पर बुलाई गई थी-'S' समूह के निदेशकों ने पहले इस्तीफा दे दिया था और 'VPP' समूह के निदेशकों को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई थी-उक्त बैठक में, कंपनी ने अपने मौजूदा सदस्यों को 1 के अनुपात में और शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा: 1 - एस और वी. पी. पी. समूह ने पहली प्रतिवादी कंपनी को विवादित कंपनी के रूप में मानने की मांग की-इसके बाद, शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक के मिनटों में

(27.01.2010) , कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी थी

2 करोड़ तक बढ़ा-वी. पी. पी. समूह और एस. समूह, याचिकाओं में अपीलार्थियों द्वारा कुप्रबंधन और उत्पीड़न के मामले को पेश करने के लिए कथित रूप से। 397 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 398-एन. सी. एल. टी. ने पाया कि शेयर पूंजी में वृद्धि और स्वयं शेयरों का आवंटन, अधिकारों के दमन का कार्य नहीं था-एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि 1 के अनुपात में आवंटन: 1 दमनकारी नहीं था-हालाँकि, जिस तरीके से आवंटन किया जाता है, वह अवैध हो सकता है और इस प्रकार,

दमनकारी हो सकता है-शेयर पूंजी में वृद्धि के कार्य को बरकरार रखा गया था-शेयरों का वितरण 'दोषपूर्ण' था-अपील पर कहा गया: कंपनी की अधिकृत पूंजी, जिसे कंपनी की नाममात्र पूंजी के रूप में भी जाना जाता है, जारी किए जा सकने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करती है-इसे ज्ञापन में इंगित किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संगठन का-इसे केवल कंपनी द्वारा पारित करके बढ़ाया जा सकता है।

एक आम निकाय की बैठक में एक प्रस्ताव-दिनांक 18.12.2009 के प्रस्ताव द्वारा, निदेशक मंडल ने वास्तव में अधिकृत पूंजी को बढ़ाने का इरादा नहीं किया था-प्रस्ताव के अंतिम पैराग्राफ की सामग्री, यह स्पष्ट करती है कि निदेशक मंडल को पता था कि अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए शेयरधारकों के सामान्य निकाय के पास शक्ति है-इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने आगे की पूंजी जारी करने का संकल्प लिया है, भले ही यह कहा जा सके कि 18.12.2009 पर, रुपये की सीमा के संदर्भ में 'आगे कोई पूंजी' मौजूद नहीं थी। 1 1 करोड़, जो 18.12.2009 पर अधिकृत पूंजी का गठन करता है-1 के अनुपात में और क्या अधिक शेयरों की पेशकश की गई है: 1 वर्तमान में

शेयरधारक-उन्हें अस्वीकार करने या कम या ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया था-यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रस्ताव निदेशकों को आगे के शेयर आवंटित करने के लिए था या

अकेले उनके समूह के सदस्य-एक समवर्ती निष्कर्ष है कि

पूंजी में वृद्धि करने का निर्णय, अर्थात्, अधिकृत पूंजी, हमले के लिए असुरक्षित नहीं थी-निर्णय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर आधारित था-निदेशक मंडल का उद्देश्य

पूंजी में वृद्धि को प्रामाणिक पाया गया है-एक आकस्मिक लाभ, अर्थात् शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन पूरी तरह से प्रतिवादी के समूहों के इनकार का अपरिहार्य परिणाम है।

समग्र रूप से, तथ्यों में, अपीलकर्ताओं को आगे के शेयरों के आवंटन के मामले में दोषपूर्ण या अनुचित तरीके से कार्य करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब - प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने के निर्णय की ईमानदारी के बारे में प्रत्यर्थियों का तर्क अपीलार्थियों के पक्ष में पाया गया है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 एक कंपनी की अधिकृत पूंजी, जिसे कंपनी की नाममात्र पूंजी के रूप में भी जाना जाता है, का प्रतिनिधित्व करती है - जारी किए जा सकने वाले शेयरों की अधिकतम संख्या। होना ही चाहिए।

एसोसिएशन के ज्ञापन में संकेत दिया गया है। इसे केवल कंपनी द्वारा आम सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अधिकृत पूंजी नहीं हो सकती है

निदेशक मंडल द्वारा बढ़ाया गया। यह अधिकृत पूंजी से बाहर है कि एक कंपनी शेयर जारी करती है। यह तब मुद्रा बन जाता है

पूँजी। जो भी जारी किया जाता है, उसकी सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है।

जो भी हो, हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। अम्बिका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड।

अभिदाता है, अभिदाता पूंजी बन जाएगी। भुगतान किया गया

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (32) में पूंजी को भुगतान के रूप में जमा की गई पूंजी के रूप में परिभाषित किया गया है। अभिदत्त पूंजी का पूर्ण या आंशिक भुगतान किया जा सकता है। [पारस 67,68] [279-डी-जी]

1.2 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 81 के तहत स्थिति समान रही क्योंकि यह केवल कंपनी है।

आवेदन पर विचार शेयरधारकों के सामान्य निकाय की विधिवत गठित बैठक में अधिकृत पूंजी में वृद्धि की प्रतीक्षा करना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करने का उचित तरीका प्रस्ताव पारित करना हो सकता था। शेयरधारकों ने अधिकृत पूंजी बढ़ाने का संकल्प लिया। यह भी उतना ही सच है कि इस तरह का प्रस्ताव 27.01.2010 पर पारित किया गया था। सवाल यह है कि क्या निदेशक मंडल के कार्य ने इसे उत्पीड़न का कार्य होने का विरोध आकर्षित किया। हम सोचेंगे कि समग्र रूप से समझे जाने वाले आई. डी. 1 पर निदेशक मंडल के निर्णयों का मतलब केवल यह है कि आगे की पूंजी जारी करने का प्रस्ताव अधिकृत पूंजी को विधिवत बढ़ाने के बाद ही प्रभावी होना था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा 81 के अधिदेश की अवहेलना करते हुए शेयरों को आवंटित करने का संकल्प लिया था। 1 के अनुपात में और अधिक शेयरों की पेशकश की गई है: 1 मौजूदा [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेयरधारक। उन्हें अस्वीकार करने या कम या ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रस्ताव निदेशकों को अतिरिक्त शेयर आवंटित करने के लिए था या अकेले उनके समूह के सदस्य। एक समवर्ती निष्कर्ष है

कि पूंजी में वृद्धि करने का निर्णय, अर्थात्, अधिकृत पूंजी, हमले के प्रति संवेदनशील नहीं थी। यह निर्णय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर आधारित था। निदेशक मंडल का पूंजी बढ़ाने का उद्देश्य प्रामाणिक पाया गया है। एक आकस्मिक लाभ, अर्थात् में परिवर्तन

शेयरधारिता का स्वरूप पूरी तरह से इनकार का अपरिहार्य परिणाम है।

आवेदन करने के लिए प्रत्यर्थी के समूहों में से। यह न्यायालय इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है कि अपीलकर्ताओं ने पूरे मामले को पहले से देखा और जानबूझकर योजना बनाई। यदि केवल उत्तरदाताओं ने आवेदन किया होता, तो स्थिति नहीं बनती। [पारस 71,72] [280-ई-एच; 281-ए-ई]

1.3 जहाँ तक इस पहलू की बात है कि कथित उद्देश्य को नए धन के सृजन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन Rs.90 लाख के स्थान पर केवल Rs.21

लाख में लाया गया था, तथ्य यह है कि भुगतान की गई पूंजी को स्पष्ट रूप से बकाया ऋणों को रद्द करके जमा किया गया था अपीलकर्ता समूह की कंपनी को इस न्यायालय को इस तथ्य की अनदेखी करने से नहीं रोकना चाहिए कि ऋण-इक्विटी अनुपात में है

निस्संदेह सुधार किया गया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि

पूरा विचार कंपनी के विस्तार के लिए बैंक से धन प्राप्त करना था। उत्तरदाताओं का मामला कि उनके कारण ऋण थे, भी उनके मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह अलग होता अगर उत्तरदाताओं ने आवेदन किया होता और कंपनी को उनके द्वारा दिए गए ऋण को रद्द करके विचार के समायोजन की मांग की होती और इसे अस्वीकार कर दिया जाता। कुल मिलाकर, तथ्यों में, अपीलकर्ताओं को आगे के शेयरों के आवंटन के मामले में दोषपूर्ण या अनुचित तरीके से कार्य करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब अधिकृत पूंजी बढ़ाने के निर्णय के प्रामाणिक होने के बारे में उत्तरदाताओं का विवाद अपीलकर्ताओं के पक्ष में पाया गया है। अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। विवादित आदेश में शेयरों को आवंटित करने का निर्देश अलग रखा जाता है। लेखापरीक्षा करने का आदेश अबाधित रहेगा।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। [पैरा 73] [281-एफ-एच; 282-ए]

नानालाल ज़वेर और एक अन्य वी। बॉम्बे लाइफ एस्योरेंस

कंपनी लिमिटेड और एक अन्य ए. आई. आर 1950 एस. सी. 172:
[1950] एस. सी. आर. 391-अनुसरण किया गया।

हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड।

डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट लिमिटेड (पी) लिमिटेड और एक और वी। पी. के

प्रतापन और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 212: [2004] 4

पूरक। एससीआर 334-प्रतिष्ठित।

नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम। सुई
इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और अन्य (1981)

3 एससीसी 333 [1981] 3 एससीआर 698-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1950] एससीआर 391

पीछा किया।

पैरा 6

[2004] 4 पूरक। एससीआर 334

प्रतिष्ठित

पैरा 21

[1981] 3 एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.8194

2018 से।

राष्ट्रीय संविधान के 02.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की कंपनी अपील (एटी) No.273 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ

2018 की सिविल अपील

No.8195।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा
हांडा, राजुल श्रीवास्तव, अनुभव शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. एस. श्रॉफ, मलक मनीष भट्ट, सिद्धार्थ,
अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
के. एम. जोसेफ, जे.

1. पहला उत्तरदाता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह भी हो सकता है

एक निकट से आयोजित निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्णित। प्रथम प्रत्यर्थी की अधिकृत पूंजी 1
करोड़ रुपये थी। इसमें दस लाख शामिल थे।

Rs.10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर। भुगतान की गई पूंजी भी वही थी। तीन समूह हैं। अपीलकर्ता 1
और 2, एक साथ और रिश्तेदारों को एच. एम. पटेल समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
उनके पास चुकता शेयर पूंजी का 30.80 प्रतिशत था। ध्यान देने योग्य अगला समूह शेठ समूह है
जिसका प्रतिनिधित्व उत्तरदाता 4 और 5 द्वारा किया जाता है। , कीर्ति कुमार ओचाच्छवलाल सेठ और
अश्विनी कुमार ओचाच्छवलाल सेठ (इसके बाद संक्षेप में 'शेठ समूह' के रूप में संदर्भित किया
जाता है)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समूह '। 2. वी. पी. पटेल समूह ने 2016 का टी. पी. 197 (2012 का सी. ए. 16) दायर किया, जबकि शेठ समूह ने 2016 का टी. पी. 10 (2010 का सी. पी. 86) दायर किया। द.

पहला उत्तरदाता कंपनी है। उत्तरदाता 2 और 3, दोनों याचिकाओं में, हमारे सामने अपीलार्थी हैं। वी. पी. पटेल समूह और शेठ समूह, उपरोक्त याचिकाओं के माध्यम से, कथित रूप से एक मामले को पेश करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर याचिकाओं में अपीलार्थियों द्वारा कुप्रबंधन और उत्पीड़न। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी., अहमदाबाद पीठ ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिकाओं का निपटारा किया:

" 92. तथ्यों के इस समूह में, कंपनी को बंद करने का आदेश देना उचित और न्यायसंगत नहीं है। यदि कंपनी को बंद करना है तो यह कंपनी के हित में नहीं है या यह शेयरधारकों के तीन समूहों के हित में नहीं है। अतः यह न्यायाधिकरण

यह देखना कि निम्नलिखित निर्देश/आदेश देना न्यायसंगत और समीचीन है

इस मामले में: -

(क) बिन्दु संख्या 3 पर निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में एक करोड़ रुपये से बढ़कर दो करोड़ सभी शेयरधारकों के लिए वैध और बाध्यकारी है। हालांकि, बढ़ी हुई शेयर पूंजी के संबंध में शेयरों का आवंटन कंपनी के सभी मौजूदा शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में 18.12.2009 पर किया जाएगा। यदि कोई शेयरधारक अतिरिक्त शेयरों के लिए अभिदान करने को तैयार नहीं है, तो उन शेयरों को अन्य शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में उनके विकल्पों को फिर से लेते हुए आवंटित किया जाएगा।

(ख) बिंदु संख्या 4 पर निष्कर्षों को देखते हुए, उत्तरदाता 2 और 3 को कंपनी के निदेशकों के रूप में हटाना वैध नहीं है।

(ग) बिन्दु सं. पर निष्कर्ष निकालते हुए। एस, यह न्यायाधिकरण निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 से कंपनी के खातों का ऑडिट किया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रत्येक द्वारा कितनी राशि की हेराफेरी की गई है।

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं 2 से 5 तक और कंपनी के सामान्य निकाय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें विधिवत रूप से अतिरिक्त सामान्य ASMUKHALAL MADHAVLAL PATEL v.

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

आम सभा। कंपनी को संबंधित व्यक्तियों से ऐसी राशि की वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। (घ) मिस। ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी, 515, लोहा भवन, सामने। पुराना उच्च न्यायालय, आयकर सर्कल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 को कंपनी के खातों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है। लेखा परीक्षक इससे पहले रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

कंपनी और उसके निदेशकों को प्रतिलिपि प्रदान करने वाले इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर यह न्यायाधिकरण। लेखापरीक्षा शुल्क अस्थायी रूप से रुपये में तय किया गया। 50,000 / - (पचास रुपया तुम केवल रेत)। लेखा परीक्षकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक मांगने की स्वतंत्रता है।

काम के बोझ पर निर्भर करता है।

(ई) यह न्यायाधिकरण स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को पहले प्रतिवादी कंपनी के शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करने का निर्देश देता है।

दाखिल करने की तिथि (CP 85/2010) TP 10/2016।

(च) ए. एस. गुप्ता एंड कंपनी, न्यू क्लॉथ मार्केट, पहली मंजिल, रायपुट गेट के बाहर, अहमदाबाद 380,002 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि इस याचिका को दायर करने की तारीख तक पहली प्रतिवादी कंपनी के शेयरों के उचित मूल्य का आकलन किया जा सके।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर भी विचार करना। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम प्रतिवादी कंपनी के शेयरों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। मूल्यांकनकर्ता उठाएगा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन का कार्य। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर इस न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेगा। शेयरधारकों में से कोई भी इस न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें कंपनी के शेयरों को बेचने के तरीके और तरीके के बारे में निर्देश/आदेश मांगे गए हैं और किसे खरीदना है और शेयरों को किस मूल्य पर बेचा जाना है।

(छ) स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता का शुल्क अस्थायी रूप से Rs.50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को काम के बोझ के आधार पर और अधिक पारिश्रमिक मांगने की स्वतंत्रता है।

(ज) इस आदेश के अनुसार पूरी प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रतिवादी सं. की चल और अचल दोनों संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। 1 किसी भी पक्ष द्वारा कंपनी।

(i) इस आदेश के अनुसार पूरी प्रक्रिया के पूरा होने तक शेयरों का कोई आवंटन या शेयरों का हस्तांतरण या बिक्री [2023] नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिवाय इसके कि जैसा इस क्रम में बताया गया है।
(जे) कंपनी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता और लेखा परीक्षकों का शुल्क वहन करेगी।

(के) दोनों याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है। इस बारे में कोई आदेश नहीं लागत "।

4. हमने श्रीमती को सुना है। मीनाक्षी अरोड़ा, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील। दूसरी ओर, हमने वी. पी. पटेल समूह की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नितिन राय और शेठ समूह की ओर से विद्वान वकील श्री मलक मनीष भट को सुना है। 5. दोनों पक्षों के बीच विवाद की जड़ एक मुद्दे तक सीमित हो गई है। अपीलार्थी एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश पर आपत्ति जताते हैं,

एन. सी. एल. टी. के निर्देश की पुष्टि करते हुए, जिसके द्वारा कंपनी के सभी मौजूदा शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में बढ़ी हुई शेयर पूंजी के संबंध में शेयरों का आवंटन किया जाना था। एन. सी. एल. टी. के पैराग्राफ-92ए (ऊपर) में यह निर्देश दिया गया था कि यदि कोई शेयरधारक अतिरिक्त शेयरों के लिए अभिदान करने को तैयार नहीं है, तो उन शेयरों को अन्य शेयरों को आवंटित किया जाएगा।

शेयरधारक, अपने विकल्पों को फिर से लेते हुए, अपनी शेयरधारिता के अनुपात में। श्रीमती. मीनाक्षी अरोड़ा, तथ्यों के अनुक्रम के माध्यम से हमें ले जाने के बाद, इंगित करती हैं कि यह पता लगाने के बाद कि कोई कुप्रबंधन या उत्पीड़न नहीं था, जैसा कि आरोप लगाया गया था और NCLT और NCLAT

उपरोक्त मामले के संबंध में स्पष्ट रूप से गलती की है। वह प्रस्तुत करेगी कि प्रथम प्रतिवादी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अधिनियम की धारा 81 कंपनी पर लागू नहीं होती थी। फिर भी, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ताओं ने सभी मौजूदा शेयरधारकों को 1 के अनुपात में एक प्रस्ताव दिया है: 1. यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी को सलाह दी गई थी कि अधिकृत पूंजी को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसका हस्मुखलाल मढवलाल पटेल बनाम.

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

पूंजी आवश्यकताओं पर विचार किया जा सकता है, अपीलकर्ताओं ने अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने का निर्णय लिया। अधिकृत पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। वह हमें याद दिलाती हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां शेठ समूह ने अप्रैल, 2009 में बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था।

निदेशक। वे लगभग 90 लाख ले गए। उनकी गतिविधियों के कारण कंपनी को खराब मौसम का सामना करना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में, अधिकृत पूंजी में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई। यह आगे बताया गया है कि हालांकि शेठ समूह और वी. पी. पटेल समूह ने कुप्रबंधन और उत्पीड़न के कार्य के रूप में अधिकृत पूंजी बढ़ाने के निर्णय को अस्वीकार करने का प्रयास किया, विशेष रूप से, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को इसमें कोई योग्यता नहीं मिली है। इसलिए, एक बार जब पूंजी में वृद्धि अवैध या दुर्भावनापूर्ण नहीं पाई गई, तो यह समझ से परे है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि शेयरों के वास्तविक आवंटन को कैसे दूषित पाया जा सकता है। तर्क में तर्क, अर्थात्, यह तर्क दिया जाता है कि आवंटन 'दोषपूर्ण' था, असहनीय था। सभी शेयरधारकों को उनकी मौजूदा हिस्सेदारी (1:1) के अनुपात में शेयरों के लिए आवेदन करने का समान अवसर दिया गया था। वे कम संख्या में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे अधिक संख्या में शेयरों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अंत में, वे किसी भी शेयर के लिए आवेदन नहीं करने के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। यह विकल्प तीनों समूहों में आने वाले बोर्ड के सभी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराया गया था। तथ्य यह है कि शेठ समूह और वी. पी. पटेल समूह ने आवेदन नहीं किया। अन्यथा कोई अवैधता पाए बिना, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी., यह तर्क दिया जाता है, स्पष्ट रूप से गलत है।

6. इसके विपरीत, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नितिन राय इंगित करेंगे कि न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पहला प्रतिवादी एक करीबी है आयोजित कंपनी। यह कमोबेश एक अर्ध-साझेदारी है और यह विश्वास पर चलती है। कंपनी की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये थी। इसके बिना

कंपनी, आम सभा की बैठक में, अधिकृत पूंजी बढ़ाने का संकल्प लेते हुए, कोई शेयर नहीं थे, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा आवंटित किया जा सकता था। इस संबंध में उन्होंने समर्थन मांगा।

इस न्यायालय के निर्णय ने नानालाल ज़वेर और एक अन्य v में रिपोर्ट किया। बॉम्बे लाइफ एस्योरेस कंपनी लिमिटेड और अन्य 1. अन्य में शब्दों में, अधिकृत पूंजी को सामान्य निकाय के निर्णय से बढ़ाया गया था, केवल 27.01.2010 पर। हालांकि, निदेशक मंडल ने उन शेयरों को आवंटित करने का फैसला किया, जो 27.01.2010 से पहले अस्तित्व में नहीं थे। निदेशक मंडल की कार्रवाई अनधिकृत और कानूनी रूप से अस्वीकार्य थी। उन्होंने आगे बताया कि यहां तक कि वी. पी. पटेल समूह और शेठ भी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समूह ने कंपनी पंजीयक के साथ औपचारिक तरीके से अपने विवाद को प्रकट और प्रकट किया था। अपीलार्थियों के लेन-देन के कारण, दोनों पक्षों के बीच टकराव था। हालाँकि, भेजे गए नोटिस की सामग्री विवादित थी, हालाँकि, मामले को दबाया नहीं गया। यह भी तर्क दिया जाता है कि एन. सी. एल. टी. ने आवंटन को त्रुटिपूर्ण पाया है। यही कारण है कि

कि कानून के तहत, जब निदेशक मंडल द्वारा आगे के शेयरों का आवंटन किया जाता है, तो शेयरों के आवंटन का सवाल, जो शेयरधारकों द्वारा नहीं लिया जाता है, केवल तब उठाया जाना चाहिए जब शेयरधारक पहले आवंटन को अस्वीकार कर दें। दूसरे शब्दों में, इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने प्रारंभिक आवंटन के साथ-साथ एकल निर्णय और नोटिस में शेयरों के आगे के आवंटन से संबंधित मुद्दे को भी शुरू कर दिया है। एनसीएलटी ने

इस मामले पर नाराज़गी जताई और ठीक ही कहा। यदि विवादित निर्देश को बरकरार रखा जाता है तो कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा। उन्होंने यह तर्क दिया कि कंपनी के शेयरों का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था और इसे समान रूप से जारी किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के समवर्ती निर्देशों को बरकरार रखने से निराश हों।

7. श्री मलक मनीष भट श्री नितिन राय द्वारा संबोधित तर्कों को प्रतिध्वनित करेंगे। यह तथ्य कि कंपनी निकटता से आयोजित परिवार है और

समूह इकाई, तनावग्रस्त है।

हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

विश्लेषण

8. 24.11.2009 पर, अपीलार्थियों द्वारा दिए गए सावधि ऋण के प्रस्ताव के जवाब में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निस्संदेह निम्नलिखित जानकारी दी:

" 1. हम आपको न्यूनतम स्तर के लिए शेयर पूंजी बढ़ाने की सलाह देते हैं।

Rs.2Crsl

2. हम आपको निदेशक मंडल का विस्तार करने की सलाह देते हैं ताकि बैंक के जोखिम को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पात्र की व्यक्तिगत गारंटी बैंक को उपलब्ध हो सके।

3. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें अपनी बैलेंस शीट में उल्लिखित आरक्षित और अधिशेष का पूरा विवरण 31.03.2009 के रूप में बताएं।

9. 08.12.2009 पर, पहली उत्तरदाता कंपनी अपने निदेशकों को एक सूचना भेजती है, जिनकी संख्या चार है। , अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 2 और 3 (वी. पी. पटेल समूह)। यह याद रखना चाहिए कि शेठ समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों ने वर्ष की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। यह बैठक 18.12.2009 पर बुलाई गई थी। बैठक के एजेंडा में, हम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पाते हैं:

4. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने पर विचार करना।
रु. 1,00,00,000/- से रु. 2,00,00,000/- तक।

10. यह बैठक 18.12.2009 पर हुई थी। वी. पी. पटेल समूह के निदेशक। , मनीष पटेल और कुणाल पटेल को छुट्टी दे दी गई है। प्रथम अपीलार्थी ने बैठक की अध्यक्षता की। दूसरा अपीलार्थी निदेशक के रूप में दूसरा प्रतिभागी था। बैठक के कार्यवृत्त निम्नलिखित हैं:

" अम्बिका खाद्य उत्पाद निजी लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त 18 दिसंबर, 2009 को राजोदा पीओ में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में। बावला-382 220

अहमदाबाद ए. टी. <आई. डी1> ए. एम.

निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. श्री हसमुखभाई माधवलाल पटेल।

2. श्री दिलीपकुमार एम. पटेल

1. बैठक के अध्यक्ष

श्री हसमुखलाल पटेल ने उपस्थित निदेशकों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता की।

2. एब्सेंस छोड़ें

3. बैंकॉफ बड़ौदा से प्राप्त पत्र पर ध्यान दें: बोर्ड को सूचित किया गया कि कंपनी को 24 नवंबर, 2009 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सेदारी लाने की सलाह दी गई है। 100 प्रस्तावित सावधि ऋण आवेदन के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाख। पहचान के उद्देश्य के अध्यक्ष द्वारा विधिवत शुरू किए गए बैंक से प्राप्त पत्र की प्रति बोर्ड के समक्ष रखी गई थी। बोर्ड ने इस पर भी ध्यान दिया।

4. समानता को बढ़ाने के लिए नैतिकता का निर्णय लेना।

रु. के शेयर। 10 / - प्रत्येक धारित शेयर के लिए एक शेयर के अनुपात में मौजूदा शेयरधारकों के अनुसार। यह सुनिश्चित किया गया कि शेयरधारकों को आवेदन करने का अधिकार होगा और किसी अन्य शेयरधारक द्वारा शेयरों की सदस्यता नहीं लिए जाने की स्थिति में अतिरिक्त शेयर लेने के इच्छुक शेयरधारक को आवंटित किया जाएगा।

हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

आगे हल किया कि शेयरधारकों को आमंत्रित करने वाला एक नोटिस इस संबंध में शेयरधारकों को उनकी पात्रता भेजी जाए और कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी होने पर आवंटन के लिए इसी पर विचार किया जाएगा।

बढ़ा दिया "।

11. इस निर्णय के बाद, 27.01.2010 पर आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक की सूचना दी गई। शेयरधारकों को सूचित किया गया था

कि 18.12.2009 पर बैठक में निर्णय के अनुसार, कंपनी ने प्रस्ताव दिया

1 के अनुपात में अपने मौजूदा सदस्यों को और शेयर जारी करना: 1 . इच्छुक सदस्यों को इस पर या उससे पहले अपने अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता थी 05.02.2010 . इसके बाद, इसे इस प्रकार दर्शाया गया था:

" कृपया ध्यान दें कि यह आवेदन करने के लिए अग्रिम सूचना और पात्रता है

शेयरों के लिए 27 जनवरी, 2010 को होने वाली ई. जी. एम. में शेयरधारकों द्वारा अधिकृत पूंजी में वृद्धि की मंजूरी दी जाएगी। शेयर आवेदन के लिए आवेदन पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

12. विशेष व्यवसाय, अर्थात् , अधिकृत पूंजी को बढ़ाना निर्दिष्ट किया गया था। अध्यक्ष के रूप में प्रथम अपीलार्थी को भी इसके लिए अधिकृत किया गया था -

संकल्पों को प्रभाव दें।

13. दिनांक 18.12.2009 के निर्णय के अनुसार, पहली प्रत्यर्थी कंपनी में इक्विटी शेयरों को आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पर ध्यान दिया जा सकता है:

" आवेदन फॉर्म

अम्बिका खाद्य उत्पाद निजी लिमिटेड
एनएच-8, विल। रायोडा: तलुका: बावला: जिला: अहमदाबाद

पिन: 382220

18 दिसंबर, 2009 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अंबिका फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में आवंटित इक्विटी शेयरों को लागू करने और प्राप्त करने के लिए आवेदन। शेयरधारक का नाम -

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रखे गए शेयर की संख्या: इक्विटी शेयर of Rs.10/- प्रत्येक बराबर पर आवेदन के लिए पात्र
शेयरों की संख्या:

इक्विटी शेयर

उपयोग किए जाने वाले विकल्प पर ध्यान दें:

- कृपया नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प पर टिक करें

- केवल एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। - सही और एक से अधिक चयन फॉर्म
को अमान्य कर देंगे और यह माना जाएगा कि अंतिम विकल्प का प्रयोग किया गया है।

- किसी भी विकल्प का चयन न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि अंतिम विकल्प का प्रयोग
किया गया है।

1. मैं/हम उन शेयरों की पूरी संख्या के लिए आवेदन करना चाहते हैं जिनके लिए मैं/हम पात्र हैं।

/ - हमारी ओर

ए। मैं/हम इसके साथ रुपये की राशि संलग्न करते हैं। डी. डी./पी. ओ./चेक सं. दिनांकित के
माध्यम से सदस्यता राशि

2010 द्वितीय।

बी। हम एतद्वारा कंपनी को राशि को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करते हैं

/ - में हमारे श्रेय के लिए खड़े

रुपये की असुरक्षित जमा राशि। कंपनी की किताबें।

इक्विटी शेयर जिनसे मैं

2. हम कम संख्या के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हम पात्र हैं।

ए। हम इसके साथ डी. डी./पी. ओ./चेक संख्या दिनांक 1/2010 के माध्यम से अपनी सदस्यता
राशि के लिए रु./- की राशि संलग्न करते हैं।

बी। हम एतद्वारा कंपनी को रुपये की असुरक्षित जमा राशि को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत
करते हैं। / - कंपनी की पुस्तकों में हमारे श्रेय के लिए सैंडिंग।

3. हम उच्चतर संख्या के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इक्विटी शेयर जिनसे मैं/हम पात्र हैं।

/ - हमारी ओर

ए। मैं/हम इसके साथ रुपये की राशि संलग्न करते हैं।

डी. डी./पी. ओ./चेक सं. दिनांक आई.

12010 के माध्यम से सदस्यता राशि।

असमूखलाल माधवलाल पटेल बनाम। अम्बिका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बी। हम एतद्वारा कंपनी को राशि को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत करते हैं
रुपये की असुरक्षित जमा राशि। / - में हमारे क्रेडिट के लिए सैंडिंग
कंपनी की किताबें।

4. हम कंपनी के किसी भी शेयर के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं।

मैं/हम इसके लिए आवेदन किए गए इक्विटी शेयरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।

ऐसी छोटी संख्या जो मुझे/हमें आवंटित की जा सकती है

आवेदन पत्र की शर्तें और संघ के लेख

कंपनी।

मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और

इक्विटी शेयरों के धारक (ओं) के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो मुझे/हमें आवंटित किया
जाए। मैंने/हमने आपको अपना नाम रखने के लिए अधिकृत किया है

के धारक के रूप में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर

इक्विटी शेयर और पंजीकरण और पता (एस) जैसा कि नीचे दिया गया है।

हम नोट करते हैं। कि निदेशक मंडल अपने पूर्ण अधिकार में है

इस आवेदन को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार

मैं/हम नियमों के अधीन शेयरों के आवंटन के लिए सहमत हैं, वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित
विनियम और शर्तें,

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यदि कोई हो और निदेशक मंडल

कंपनी से।

मैं/हम भारत में भारतीय नागरिक (ओं) निवासी हैं और 1 बजे/हम हैं

किसी भी निवासी व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति के रूप में इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन नहीं करना
विदेश में या कोई विदेशी नागरिक।

(प्रथम धारक का हस्ताक्षर)

(दूसरे धारक का हस्ताक्षर)

(तीसरे धारक का हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

ध्यान दें:

उपरोक्त हस्ताक्षर अभिलेख पर हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए।

14. 18.12.2009 पर, दूसरा उत्तरदाता, अर्थात् , मनीष कुमार

टेल, ने कंपनियों के पंजीयक, गुजरात को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि पहली प्रतिवादी कंपनी को एक विवादित कंपनी के रूप में चिह्नित किया जाए और नहीं

ई-प्रपत्र सहित कोई भी दस्तावेज, कागजात, प्रपत्र, अभिलेख में, [2023] 8 एस. सी. आर. के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुमत के प्रति निर्णय पर विचार नहीं किया जाता है। पत्र में कहा गया है कि

वे अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित रहेंगे। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता अधिकृत पूंजी बढ़ा सकते हैं और उन्हें शेयर आवंटित कर सकते हैं और धोखाधड़ी से कंपनी का नियंत्रण ले लें। यह आगे कहा गया है कि वे शेयरधारकों को सूचित करने और एम. सी. ए.-21 पोर्टल से अपीलकर्ताओं को हटाने का संकल्प लेने के लिए जल्द ही आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक बुलाने की प्रक्रिया में थे और उसी के साथ <आई. डी. 2] का रिकॉर्ड, शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित एक संचार, जिसमें शेठ समूह और वी. पी. पटेल समूह को जोड़ा गया था और जिसमें 68.98 प्रतिशत शेयर शामिल थे, जिसमें पहली प्रतिवादी कंपनी को विवादित कंपनी मानने की मांग करने वाले पत्र का समर्थन किया गया था।

इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। उसी दिन निदेशक मंडल की एक बैठक हुई। अपीलार्थियों ने बैठक में भाग लिया। उत्तरदाता 2 और 3 को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई थी। हम पाते हैं। उक्त बैठक के कार्यवृत्त से निम्नलिखित:

" निदेशकों की बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त
अम्बिका खाद्य उत्पाद। सीमित पकड़

अहमदाबाद ए. टी. <आई. डी1> पी. एम.
निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री हसमुखभाई माधवलाल पटेल।

2. श्री दिलीपकुमार एम. पटेल

1. बैठक के अध्यक्ष

श्री हसमुखलाल

पटेल ने उपस्थित निदेशकों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता की।

2. लीवऑफ़ एब्सेंस

श्री मनीष पटेल, निदेशक और Mr.Krunal पटेल, निदेशक को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई थी।

3. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल से बाहर

आएं

बैठक:

असमूखलाल माधवलाल पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बोर्ड को सूचित किया गया कि कंपनी के शेयरधारक अधिकृत हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए सामान्य संकल्प को पार कर लिया है

कंपनी की पूँजी रु. 1,00,00,000 / - रु. तक। 2,00,00,000 / - . बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया है। निदेशक में से कोई भी

कंपनी को तब आवश्यक फॉर्म 5 दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया था

कंपनी पंजीयक के कार्यालय के साथ। 4. शेयरों के आवंटन के लिए बोर्ड बैठक: प्रोप

बोर्ड को सूचित किया गया कि जैसा कि उल्लेख किया गया है, शेयर धारक

कंपनी ने अधिकृत राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 तारीख है फरवरी, 2010। अतएवं ऐसा है। बैठक बुलाने का प्रस्ताव

निदेशक मंडल ने प्रस्ताव दिया। 9 फरवरी, 20 को आयोजित किया जाएगा

10 , इक्विटी शेयरों के आगे जारी करने के आवंटन पर विचार करने के लिए।

बोर्ड ने इस मामले को खारिज कर दिया और बोर्ड की बैठक आयोजित करने का फैसला किया

9 फरवरी, 2010 को। बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि

कंपनी शेयरधारकों को इसके बारे में सूचित करने के लिए कदम उठा रही है बैठक का परिणाम ताकि वे तत्काल कदम उठा सकें

इक्विटी की सदस्यता लें।

5. धन्यवाद का वोट:

कुर्सी का धन्यवाद। तारीख: 27.01.2010

निदेशक

(हसमुखभाई पा टेल)

अध्यक्ष "

(जोर दिया गया)

16. उसी के अनुसार, यह अपीलार्थियों का विशिष्ट मामला है

शेयरधारकों को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजे गए थे

असाधारण आम सभा की बैठक ताकि वे कर सकें अतिरिक्त पूंजी की सदस्यता लेने के लिए कदम उठाए जाने की मांग की गई। वहाँ विलेख, नोटिसों का सबूत। यह सच है कि उत्तरदाता अभी भी

उसी की रसीद।

17. 09.02.2010 पर, हम बैठक के निम्नलिखित कार्यवृत्त पाते हैं

उक्त तिथि का निदेशक मंडल:

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अहमदाबाद ए. टी. <आई. डी1> ए. एम. निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री हासमुकीभाई माधवलाल पटेल।

2. श्री दिलीपकुमार एम. पटेल

1. बैठक के अध्यक्ष

श्री हसमुखलाल पटेल ने उपस्थित निदेशकों की सहमति से बैठक की अध्यक्षता की।

2. एब्सेंस छोड़ें

श्री मनीष पटेल, निदेशक और श्री कृणाल पटेल, निदेशक को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई।

3. सहरों का आवंटन:

बोर्ड को सूचित किया कि कंपनी को 7 प्राप्त हुए हैं

यह शेयरधारकों से आवेदन करता है, जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई है

को। बोर्ड ने तब प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया और उसी क्रम में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

केवल) @प्रति होगा और इसके द्वारा आवेदकों को निम्नानुसार आवंटित किया गया है: श्री.
नहीं। एल्लोटी का नाम

का नाम

आवंटित साझा करें

हिमांशु माधवलाल पटेल

1 .

165000

वर्षाबिन हसमुखलाल पटेल

140000

2 .

दिलीप कुमार माधवलाल पटेल

3 .

149000

ज्योत्सना दिलीप कुमार पटेल

4 .

185000

निसतगकुमार हसमुखलाल पटेल

5 .

92000 हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

बंकिमकुमार दिलीपकुमार पटेल

6 .

71000

7 .

दिशाबेन हसमुखलाल पटेल

98000

कुल

900000

हल किया गया कि कंपनी जारी करना आवश्यक है

और श्री हसमुखलाल पटेल और श्री दिलीप कुमार पटेल सामान्य मुहर के तहत उक्त प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कंपनी ने।

हल किया गया कि आवश्यक वापसी

प्रपत्र 2 में आवंटन कंपनी पंजीयक के पास दाखिल किया जाए,

गुजरात।

तारीख: 09.02.2010

निदेशक

(हसमुखभाई पटेल)

अध्यक्ष "

एन. सी. एल. टी. के परिणाम

18. इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भुगतान में वृद्धि हुई है

बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए और दिनांक 24.12.2009 की असाधारण आम बैठक की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी। न्यायाधिकरण ने पाया कि वी. पी. पटेल समूह के शेयरधारकों को

इसकी जानकारी थी शेयर पूँजी बढ़ाने का प्रस्ताव। शेठ समूह ने भी, ज्ञान के साथ, [2023] 8 एस. सी. आर. पर बोर्ड की बैठक में भाग लेने का विकल्प नहीं चुना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैठकों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कंपनी अधिनियम और संघ के अनुच्छेदों के प्रावधानों का पालन करने के बाद, अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके अनुसार, शेयरधारकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। हिस्सेदारी में वृद्धि वी. पी. पटेल समूह की आपत्तियों के कारण कंपनियों के पंजीयक के पास कोई विवरणी दर्ज नहीं किए जाने के कारण पूंजी और आवंटन को प्रभावी नहीं किया गया था। इसलिए, शेयर पूंजी में वृद्धि

और स्वयं शेयरों का आवंटन और स्वयं शेयरों का आवंटन, वी. पी. पटेल समूह और शेठ समूह के अधिकारों के दमन का कार्य नहीं है, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा पाया जाता है। यह भी पाया गया है कि निर्देशानुसार अपीलार्थियों को हटाना वैध नहीं था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था। इसके तहत

बिन्दु, 'तीन समूहों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं का परिणाम', यह पाया गया है कि तीन समूह आपस में भिड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों समूहों के एक साथ आने और पहली प्रत्यर्थी कंपनी के मामलों का संचालन करने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद यह बताया गया है कि न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से पता चलता है कि उत्पीड़न के कोई स्थापित कार्य नहीं हैं

और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को छोड़कर कुप्रबंधन, जिसके लिए निदेशक मंडल द्वारा जांच की आवश्यकता होती है। इसके बाद, हमने पैराग्राफ-92 (ऊपर) में दिए गए निर्देशों पर ध्यान दिया है। 19. इसके बाद, आवंटन के संबंध में विवादित आदेश में निष्कर्ष है। एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी पाया कि शेठ समूह और वी. पी.

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए 24.11.2009 दिनांकित पत्र सहित, अपीलार्थियों द्वारा प्रचार की गई पूंजी और परिस्थितियाँ, जिनके कारण यह हुआ, विश्वसनीय पाई गई। हमारे समक्ष अपीलों से संबंधित बिंदु, अर्थात् शेयर पूंजी की वृद्धि पर शेयरों के वास्तविक आवंटन पर विचार करते हुए, यह पाया गया कि शेयरों के आवंटन के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा कोई चर्चा नहीं हुई है। 20. इसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि 1 के अनुपात में आवंटन: 1 दमनकारी नहीं हो सकता है, यह पाया जाता है। हालाँकि, जिस तरह से आवंटन किया जाता है, वह अवैध और इस प्रकार दमनकारी हो सकता है। एनसीएलटी की दिशा

अभिलेखों में आधारहीन नहीं पाया गया।

हसमुखलाल माधवलाल पटेल v. एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए, यह नोट किया जाता है कि वे दिनांकित 04.02.2010 हैं और वे दिखाते हैं कि आवेदन 1 के अनुपात में नहीं थे: 1 लेकिन उससे कहीं ज्यादा। उदाहरण के लिए, यह कहा गया है कि पहले अपीलार्थी की पत्नी के पास केवल 20 इक्विटी शेयर थे। उन्होंने 98000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया। वी. पी. पटेल समूह का यह तर्क कि अपीलकर्ता समूह के सदस्यों ने पहले से गणना की और आवेदन किया ताकि वे पूरी बढ़ी हुई शेयर पूंजी का उपभोग कर सकें, यह पहले से अनुमान लगाते हुए कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान में रखा जाता है। संघ के अनुच्छेदों का एक संदर्भ दिया गया था और उसमें सामान्य प्राधिकरण का उल्लेख करने वाले निम्नलिखित अनुच्छेद को संदर्भित किया गया है

निम्नलिखित है:

" सामान्य प्राधिकरण

जहां कहीं भी कंपनी अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी को कोई अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार होगा या वह कंपनी कोई लेनदेन नहीं कर सकती है जब तक कि कंपनी अपने अनुच्छेदों द्वारा अधिकृत नहीं है, तो उस मामले में, अनुच्छेदों द्वारा कंपनी को ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार प्राप्त करने और ऐसे लेनदेन को करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया जाता है जो किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अनुमत।

21. यह तर्क कि अनुच्छेद की धारा 81 को ध्यान में रखते हुए

अधिनियम लागू होगा, यह नोट किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि भले ही अपीलकर्ताओं ने सदस्यों की अपेक्षा में शेयर पूंजी की वृद्धि पर आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया था, जो उस समय तक तय नहीं किया गया था, प्रस्ताव 1 से अधिक का नहीं हो सकता था: 1 और सही प्रक्रिया यह रही होगी कि शेयर पूंजी बढ़ाने के बाद, 1 के दावे: 1 इस पर विचार किया जाना चाहिए था और उसके बाद ही, सदस्यता रद्द किए गए हिस्से की पेशकश की जा सकती थी। तर्क डेल और कैरिंगटन प्राइवेट पर आधारित है। (पी) लिमिटेड और एक अन्य वी। पी. के. प्रतापन और अन्य 2 का उल्लेख किया गया।

22. इसके बाद यह पाया गया कि शेयर पूंजी में वृद्धि के कार्य को बरकरार रखा जा सकता है। शेयरों का वितरण 'दोषपूर्ण' था। भले ही

शेयर पूंजी में वृद्धि की प्रत्याशा, यदि पहले से रखे गए शेयर के अनुपात में आवेदन किए जा सकते हैं, लेकिन बिना सदस्यता वाले शेयरों का निपटान केवल तभी किया जा सकता है जब शेयरधारक ने प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। इसके लिए, यह पाया गया है कि इसमें

आवेदन नहीं हो सकते थे प्रतीक्षा करें। इसके बाद यह पाया गया कि उचित और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 09.02.2010 दिनांकित बोर्ड प्रस्ताव को बरकरार नहीं रखा जा सका।

2 (2005) 1 एससीसी 212 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. एन. सी. एल. टी. के निर्देश को बरकरार रखा गया।

24. हम देख सकते हैं कि वी. पी. पटेल समूह और सेठ समूह का मामला कुप्रबंधन और उत्पीड़न के आधार पर

अन्यथा, अपीलार्थियों को खारिज कर दिया गया है। यह शिकायत भी खारिज कर दी गई है कि जब कंपनी ने अधिकृत पूंजी बढ़ाने का फैसला किया तो अपीलकर्ताओं ने दमनकारी तरीके से काम किया या कंपनी का कुप्रबंधन किया। एन. सी. एल. टी. ने वी. पी. पटेल समूह और सेठ समूह को शेयर आवंटित करने के निर्देश के लिए कोई तर्क नहीं दिया है, जैसा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ऊपर उल्लिखित आधार पर दिशा का समर्थन करता है।

25. श्री नितिन राय ने इस बात पर जोर दिया कि निदेशक मंडल शेयरों का आवंटन नहीं कर सकता था, जब मौजूदा अधिकृत पूंजी पहले से ही अभिदानित थी और इसके अलावा, भुगतान किया गया था। गाड़ी को घोड़े के सामने रखते हुए, शेयरधारकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे

उन शेयरों के लिए आवेदन करें जो मौजूद नहीं थे। दूसरे शब्दों में, आई. डी. 1 के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा की बैठक में अधिकृत पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने के निर्णय के बाद ही बोर्ड आवेदन आमंत्रित करने का संकल्प ले सकता था। इस संबंध में, उन्होंने नानालाल ज़वेर और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त किया। बॉम्बे लाइफ एस्योरेस कंपनी लिमिटेड और अन्य 3.

26. नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य में रिपोर्ट किए गए निर्णय में v. नीडल इंडस्ट्रीज न्यू (इंडिया) होलिंग लिमिटेड और अन्य, हम निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देते हैं:

" 110. इस विषय को छोड़ने से पहले, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि केवल ऐसी परिस्थिति जिसमें निदेशकों को लाभ प्राप्त होता है

शेयर जारी करना, उस शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करेगा। जैसा कि गोवर द्वारा आधुनिक कंपनी कानून के सिद्धांतों में देखा गया है, चौथा संस्करण। , पी। 578 : " जैसा कि एक ऑस्ट्रेलियाई मामले में खुशी से कहा गया था कि उन्हें "कानून द्वारा अलग परोपकार के अवास्तविक क्षेत्र में रहने और स्पष्ट तथ्यों से आदर्श अमूर्तता के अस्पष्ट मनोदशा में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जो किसी भी ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में मौजूद होना चाहिए।

जब वह एक निदेशक के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

3 AIR 1950 SC 172/1950 SCC 137 4 (1981) 3 SCC 333 ASMUKHLAL MADHAVLAL
PATEL v.

अम्बिका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

विद्वान लेखक द्वारा ऊपर संदर्भित ऑस्ट्रेलियाई मामला

मिल्स वी है। मिल्स [60 सी. एल. आर. 150,160] जो विशेष रूप से था

हार्वर्ड स्मिथ में लॉर्ड विल्बरफोर्स द्वारा अनुमोदित [1974 एसी 821, 831] . नानालाल ज़वेर में [1950 एस. सी. सी. 137: ए. आई. आर 1950 एस. सी 172:

1950 एस. सी. आर. 391,394] भी, दास, जे. ने पी. में कहा। 425 कि सच है

प्रिवी की न्यायिक समिति द्वारा सिद्धांत निर्धारित किया गया था

हिर्श बनाम में परिषद। सिम्स [1894 एसी 654,660-61: 64 एलजे पीसी 1:

71 एलटी 357: 10 टीएलआर 616] इस प्रकार:

जिस कंपनी का वे प्रचार भी कर रहे थे, या क्योंकि बाद में उन्होंने उन कीमतों पर शेयर बेचे जिनसे उन्हें बड़ा फायदा हुआ।

लाभ "।

111. क्या कोई इस मामले को दृष्टिकोण से देखता है

इस न्यायालय द्वारा नानालाल ज़वेर [1950 एस. सी. सी. 137 ए. आई. आर.] में व्यक्त किया गया

1950 एससी 172: 1950 एस. सी. आर. 391,394] या दृष्टिकोण से

हार्वर्ड स्मिथ में प्रिवी काउंसिल द्वारा व्यक्त किया गया [1974 एसी 821,

831] परीक्षण एक ही है, अर्थात्, क्या शेयरों का निर्गम है

केवल या केवल निदेशकों के लाभ के लिए। अगर शेयर हैं

कंपनी के व्यापक हित में जारी किया गया, जारी करने का निर्णय

शेयरों को इस आधार पर कम नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने संयोग से

निदेशकों को शेयरधारकों के रूप में उनकी क्षमता में लाभ हुआ। हमें करना चाहिए,

इसलिए, श्री सीरवर्ड के इस तर्क को अस्वीकार करें कि तत्काल मामले में,

निदेशक मंडल ने निर्णय लेने में अपनी प्रत्ययी शक्ति का दुरुपयोग किया

राइट्स शेयरों के मुद्दे पर "।

(जोर दिया गया)

27. जबकि उक्त निर्णय पर, हम इसे उचित पाते हैं कि

श्री नितिन राय, विद्वान वरिष्ठ वकील की शिकायत है कि

एस का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था और उन्हें निम्नलिखित विवरण के बिना जारी किया गया था:

" 120. अंत में, कानून के एक कथन के रूप में यह कहना भी सही नहीं है कि

निदेशकों के पास समान दर पर शेयर जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, यदि उनका बाजार

कीमत बराबर से ऊपर है। ये मुख्य रूप से नीति के मामले हैं

निदेशकों को अपने विवेक के प्रयोग में निर्णय लेना चाहिए और कोई कठिन निर्णय नहीं लेना चाहिए और उस विवेक को बाधित करने के लिए त्वरित नियम निर्धारित किया जा सकता है।

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिल्डर वी में लॉर्ड डेवी द्वारा। डेक्सटर [(1902) एसी 474,480: 71 एलजे सीएच 781 87 एलटी 311: 18 टीएलआर 800]: " मुझे किसी कानून की जानकारी नहीं है।

जो एक कंपनी को अपने शेयरों को बराबर से ऊपर जारी करने के लिए बाध्य करता है क्योंकि वे बाजार में प्रीमियम पर बिक्री योग्य हैं। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि यह विवेकपूर्ण होगा या नहीं।

ऐसा करना संभव है, और यह निदेशकों को तय करने का सवाल है। ध्यान में रखने की आवश्यकता यह है कि ऐसी विवेकाधीन शक्तियाँ कंपनी प्रशासन में प्रत्ययी शक्तियों की प्रकृति होती है

और, इस कारण से, सद्भावना से प्रयोग किया जाना चाहिए। माला ऐसे विवेक के प्रयोग को दूषित करती है। हम उल्लेख कर सकते हैं कि अतीत में, जब भी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता महसूस की गई थी, या अन्य कारणों से, एन. आई. आई. एल. ने अपने सदस्यों को समान रूप से शेयर जारी किए थे।

28. इस तथ्य के अलावा कि, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि श्री नितिन राय ने निष्पक्ष रूप से कहा था कि इस मुद्दे का इस तरह से आग्रह नहीं किया गया था, कानून का उपरोक्त बयान अदालत को आश्चस्त करता है कि उक्त तर्क में भी तथ्यों में कोई योग्यता नहीं हो सकती है।

29. इसके बाद, हम डेल एंड में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं।

कैरिंगटन प्राइवेट। (पी) लिमिटेड (ऊपर)। उक्त मामले को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा संदर्भित किया गया है और साथ ही उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील भी। इस न्यायालय ने यह विचार रखने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है कि एक निजी लिमिटेड कंपनी के निदेशकों का परीक्षण बहुत सूक्ष्म पैमाने पर किया जाना चाहिए ताकि इस बात से इंकार किया जा सके कि

सत्ता का दुरुपयोग। न्यायालय ने कहा:

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशकों से ऐसी कंपनी के शेयरधारकों को एक खुलासा करने की उम्मीद की जाती है जब आगे के शेयर जारी किए जा रहे हों। यह सद्भावना से कार्य करने और कंपनी के मामलों के बारे में शेयरधारकों को पूरा खुलासा करने के उनके कर्तव्य से आवश्यकता प्रवाहित होती है।

एक निजी लिमिटेड कंपनी में निदेशकों के कार्यों का बहुत सूक्ष्म पैमाने पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि व्यक्तिगत लाभ या गुप्त उद्देश्यों के लिए सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को खारिज किया जा सके। प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 81 लागू नहीं

कंपनियाँ अपने निदेशकों पर भारी बोझ डालती हैं।

प्राइवेट लिमिटेड हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड।
[के. एम. जोसेफ, जे.]

साझेदारी जहाँ भागीदारों का कर्तव्य होता है कि वे पूर्ण रूप से कार्य करें एक-दूसरे के प्रति अच्छा विश्वास रखें। धारा 81 की गैर-प्रयोज्यता

निजी कंपनियों के लिए अधिनियम का मतलब यह नहीं है कि निदेशक

मामलों के प्रबंधन के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता है

कंपनी ने। वर्तमान मामले में अनुच्छेद 4 (iii)

इससे पहले धन के दुरुपयोग के लिए विश्वासघात के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए कंपनी और उसकी परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के लिए।

(जोर दिया गया)

30. यह सच है कि अपीलार्थी के पास भुगतान का 30.80 प्रतिशत था।

साझा पूंजी। वी. पी. पटेल समूह के पास चुकता शेयर पूंजी का 24.20 प्रतिशत था। सेठ समूह के पास चुकता शेयर पूंजी का 45 प्रतिशत था। यह तब है जब कंपनी की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किए जाने के बाद स्थिति इस प्रकार है:

अपीलकर्ता-समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 63.58% हो गई है।

चुकता शेयर पूंजी। वी. पी. पटेल समूह की हिस्सेदारी

यह चुकता शेयर पूंजी का 12.74% है। शेयरधारिता

सेठ समूह का भुगतान किए गए हिस्से का 23.68% प्रतिशत है।
राजधानी।

31. अपीलार्थी मामलों के शीर्ष पर थे, निस्संदेह,

पहला उत्तरदाता-कंपनी। पहिल अपीलार्थी कम्पनीक अध्यक्ष छलाह। अप्रैल 2009 में कहीं, सेठ समूह के निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया था। निदेशक मंडल में अपीलार्थी और वी. पी. पटेल समूह से संबंधित दो निदेशक शामिल थे। एक समवर्ती निष्कर्ष है कि अपीलकर्ताओं द्वारा अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए लिए गए निर्णय को उत्पीड़न या कुप्रबंधन के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या अतिरिक्त शेयरों के आवंटन के तरीके से उत्पीड़न किया गया है।

32. पहला उत्तरदाता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अनुभाग

81 (3) अधिनियम के, प्रावधान के दायरे से स्पष्ट रूप से छूट, [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बावजूद, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट में अभिनिर्धारित किया गया है। (पी) लिमिटेड (ऊपर), निदेशकों के आचरण को एक उच्च मानदंड पर आंका जाना है। अंतिम विश्लेषण में सवाल यह होगा कि क्या निदेशकों ने कंपनी के सर्वोत्तम हित में काम किया या क्या वे कंपनी में अपनी शक्ति को मजबूत करने या कंपनी में शक्ति बनाए रखने के लिए प्रेरित थे। क्या निदेशकों ने इसमें ईमानदारी से काम किया, जब अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, तो वे कंपनी में अन्य हितधारकों को किनारे करने के इरादे से प्रेरित थे?

33. यह तथ्य कि निदेशक भी मुख्य रूप से कंपनी के हित को बढ़ावा देने के इरादे से लिए गए निर्णय से लाभान्वित हो सकते हैं, निर्णय को दूषित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि मुख्य रूप से कंपनी के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन में, अपीलकर्ताओं ने लाभ कमाया है, तो यह स्वयं निर्णय को असुरक्षित नहीं बना सकता है।

34. विवादित आदेश में एक अवलोकन पाया गया है कि पहले अपीलार्थी की पत्नी के पास 20 शेयर थे और उसे 96000 शेयर आवंटित किए गए हैं। शुरू में शर्म आने पर, यह संदेह और यहाँ तक कि सदमे की ओर ले जाता है। लेकिन, आइए हम जाँच करें कि वास्तव में क्या हुआ था। निदेशक मंडल ने अधिकृत शेयर पूंजी को रुपये से बढ़ाने का निर्णय लिया। 1 बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई सलाह का पालन करते हुए 2 करोड़ रुपये। यह समय की आवश्यकता होने के कारण एक पूरी तरह से उचित निर्णय था। चूंकि, अधिकृत शेयर पूंजी कंपनी के संगठन के ज्ञापन का हिस्सा है, इसलिए शेयरधारकों की बैठक में इसका समर्थन करने के बाद ही इसमें वृद्धि की अनुमति होगी। ऐसी बैठक बुलाई गई थी

27.01.2010 . यह सच है कि इस तरह की बैठक से पहले ही निदेशक मंडल ने शेयरधारकों से आवेदन आमंत्रित करने का संकल्प लिया था। आवेदन पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमने निकाला है। शेयरधारक, रूप के संदर्भ में, चार काम कर सकता है:

चूंकि बोर्ड ने अनुपात में शेयर आवंटित करने का संकल्प लिया था

आई.

1 : 1 , शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक शेयर के लिए आवेदन कर सकता है

उसके पास एक हिस्सा था;

आवेदन पत्र में आगे विचार किया गया कि

ii.

शेयरधारक यह संकेत दे सकता है कि वह कम संख्या में शेयरों के लिए आवेदन करना चाहता है, जिसके वह हकदार था।

एक शेयरधारक अधिक संख्या में शेयरों के लिए आवेदन कर सकता है।

iii.

वह इसके हकदार थे; हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अंत में, वह किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त कर सकते थे।

iv.

शेयर।

35. यह इस रूप की पृष्ठभूमि में है कि हमें कथा को जारी रखना चाहिए। वी. पी. पटेल समूह और शेठ समूह के शेयरधारकों ने उन्हें दिए गए अवसर का लाभ उठाते हुए आवेदन नहीं किया। उन्होंने असाधारण आम सभा की बैठक में भाग नहीं लिया 27.01.2010 पर आयोजित किया गया जिसके द्वारा अधिकृत पूंजी बढ़ाई गई थी। हालांकि कुछ विवाद उठाए जाने की मांग की गई है कि शेयरधारकों को शेयरों के लिए आवेदन करने के उनके अधिकार के अनुस्मारक के माध्यम से कोई सूचना नहीं भेजी गई थी, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि संचार वास्तव में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए भेजा गया था।

27.01.2010 पर आयोजित असाधारण आम सभा की बैठक के बाद निदेशकगण। दूसरी ओर, अपीलकर्ता समूह के सदस्यों ने शेयरों के लिए आवेदन किया। चूंकि, यह विचार किया गया था कि शेयरधारक न केवल 1 के अनुपात में आवेदन कर सकते हैं: 1 लेकिन बड़ी संख्या में शेयरों के लिए,

वी. पी. पटेल समूह और शेठ समूह से संबंधित लोगों ने भी अपनी हिस्सेदारी की तुलना में बड़ी संख्या में शेयरों के लिए आवेदन किया था और अधिक हिस्सेदारी की मांग करने वाले उनके आवेदन में कोई भेदभाव या अस्वीकृति थी। तब, वास्तव में, यह पता लगाने का एक अवसर होता कि उत्पीड़न का एक कार्य कायम रखा गया था। वी. पी. पटेल समूह और शेठ समूह के सदस्यों द्वारा किसी भी संख्या में शेयरों के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में, हम इस अधिनियम को दमनकारी के रूप में देखने या चिह्नित करने में असमर्थ हैं।

36. प्रत्यर्थियों ने बताया कि उपलब्ध धन में से लगभग 25 लाख की राशि अपीलार्थियों के सदस्य को दी गई थी समूह।

37. जहां तक अंतिम शिकायत का संबंध है, अपीलार्थी यह इंगित करेंगे कि वास्तव में जो कुछ हुआ वह अपीलार्थी-समूह द्वारा पहले लाए गए धन का पुनर्भुगतान था, जिसे कंपनी के पास रखा गया था और

परिवार के एक सदस्य की शादी के संबंध में, राशि [2023] 8 एस. सी. आर. थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लौट आए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों पक्षों के आरोप और प्रतिक्रियाएं लेखा परीक्षा का विषय हैं। हम शेयरों के आवंटन के मामले में 'दोष' या कथित अवैधता पर निर्णय लेने में उसी से विचलित नहीं हो सकते हैं।

38. डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट में तथ्य। (पी) लिमिटेड (ऊपर) हैं

स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य। मामला तथ्यों पर एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां, प्रयास पूरी तरह से विचाराधीन व्यक्ति द्वारा सत्ता को मजबूत करने और घेरने के लिए निर्देशित किए गए थे। इस मामले में, तथ्यों से, जैसा कि वर्णित है, हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि शेयरों की पेशकश मौजूदा को की गई थी। शेयरधारक और, अधिक क्या है, एक उचित और समान आधार पर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या रखते हैं।

39. उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि बोर्ड ने 27.01.2001 पर शेयरधारकों को आवेदन करने के अधिकार की याद दिलाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि नोटिस भेजे गए थे और उन्हें पेश भी किया गया था। उत्तरदाता हालांकि यह इंगित करेंगे कि कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

40. 27.01.2020 दिनांकित भेजा गया नोटिस इस प्रकार है:

" 27जनवरी, 2010

को,
शेयरधारक

संलग्न सूची के अनुसार सभी

उप. : असाधारण आम बैठक का परिणाम।

प्रिय महोदय,

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में कंपनी के सदस्य उपस्थित रहते हैं, उन्होंने वृद्धि के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित किया है रुपये से कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी। 1क्र. रु. तक।

2 क्र.

आभार व्यक्त करते हुए,

आपका सच में, हसमुखलाल माधव पटेल बनाम। एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अंबिका फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए निर्देशक "

41. अब, उत्तरदाताओं द्वारा एक तर्क लिया जाता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने यह नहीं पाया है कि इसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, हम निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं। दिनांक 24.12.2009 की असाधारण आम बैठक की सूचना के संबंध में, उत्तरदाताओं द्वारा एक तर्क लिया गया था कि डाक कवर में सूचना के कागजात नहीं थे, बल्कि कुछ अन्य संचार थे। एन. सी. एल. टी. के साथ सहमति, इसकी अस्वीकृति में उत्तरदाताओं के मामले में, एन. सी. एल. ए. टी. ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 28. बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि वी. पी. पटेल समूह और एच. एम. पटेल समूह ने एन. सी. एल. टी. से पहले यह रुख अपनाया कि भेजे गए डाक कवर नहीं थे।

नोटिस के कागजात होते हैं लेकिन उनमें कुछ अन्य होते हैं

धोखाधड़ी। हालाँकि, जैसा कि विवादित आदेश से पता चलता है, एन. सी. एल. टी. ने इन आधारों पर विवाद उठाया था और हालाँकि एन. सी. एल. टी. के सामने यह प्रदर्शित किया गया था कि लिफाफा कवर खोलने पर, उसके पास ई. ओ. जी. एम., एन. सी. एल. टी. के नोटिस के अलावा कुछ अन्य कागजात थे। जो लिफाफे दिखाए जा रहे थे, उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि उन्हें एक बार खोला गया था और

फिर से सील कर दिया। इन वादियों के इस तरह के दृष्टिकोण को देखते हुए, हम उनकी इस दलील पर भरोसा नहीं करना चाहेंगे कि उन्हें ईओजीएम का नोटिस नहीं मिला।

प्रस्ताव का लाभ उठाने से इनकार कर दिया। एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा एक समवर्ती निष्कर्ष है कि उत्तरदाताओं को प्रस्तावित शेयर पूंजी में वृद्धि के बारे में पता था। यह समवर्ती रूप से पाया जाता है कि बैठकें कानून के अनुपालन में आयोजित की गई थीं। 43. एन. सी. एल. ए. टी. का तर्क है कि भले ही पहले से रखे गए शेयरों के अनुपात में आवेदन किए जा सकते हैं, लेकिन बिना सदस्यता वाले शेयरों का निपटान तभी किया जा सकता है जब प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाए। यह आगे पाया गया है कि अपेक्षा में आवेदन नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि यह एन. सी. एल. ए. टी. की समझ है कि जबकि शेयरों के लिए 1 की सीमा तक आवेदन किया जा सकता है: 1 जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, लेकिन बोर्ड [2023] 8 एस. सी. आर. के तहत अनुमति के अनुसार उक्त अनुपात से अधिक की पेशकश किए जाने वाले शेयरों के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संकल्प दिनांक 18.12.2009, यह केवल तभी किया जाता जब एक शेयरधारक ने प्रस्तावित शेयरों को लेने से इनकार कर दिया होता। एक शेयरधारक अतिरिक्त शेयरों के लिए यह अनुमान लगाते हुए आवेदन नहीं कर सकता था कि अन्य शेयरधारक प्रस्तावित शेयरों को नहीं लेंगे।

44. अब, कानून में, आइए पहले इस आधार पर आगे बढ़ें कि प्रस्ताव अधिकृत पूंजी के साथ इस तरह से किया गया था कि स्वीकृति प्रस्ताव की पूंजी को अधिकृत पूंजी के भीतर रखा जाएगा।

45. एक रोलड-अप प्रस्ताव में निम्नलिखित परिणाम शामिल होंगे:

एक शेयरधारक बिल्कुल भी आवेदन नहीं करने के लिए स्वतंत्र था। एक शेयरधारक 1 के अनुपात से कम के लिए आवेदन कर सकता है: 1. वह 1 के अनुपात के अनुसार शेयरों के लिए आवेदन कर सकता है: 1. अब, वह आवेदन पत्र के तहत आवेदन कर सकता है अधिक हिस्सेदारी। कोई सीमा नहीं थी। कानून में जिस कानूनी सीमा को पार किया जाना है, वह विवाद में नहीं है। कानून में विचार किया गया है कि शेयरों को जारी किए गए शेयरों के 90 प्रतिशत तक अभिदान किया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसे 90 प्रतिशत तक अभिदान दिया गया था। 1 के अनुपात से अधिक के शेयरों सहित, सभी शेयरधारकों को पहले बताए गए शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए 'समान रूप से' अनुमति देकर: 1, हमें ऐसा कोई कानून नहीं दिखाया गया है जिसका उल्लंघन हुआ हो। यदि सभी शेयरधारकों ने पात्रता से अधिक आवेदन किया होता, तो अनिवार्य रूप से बोर्ड वास्तव में उचित और समान आधार पर शेयरों को वितरित करने के लिए बाध्य होता। यह आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि उत्तरदाताओं ने बिल्कुल भी आवेदन नहीं किया। यदि उत्तरदाता समूह के कुछ लोगों ने आवेदन किया होता, तो फिर से आवंटन का परीक्षण किया जाता।

निष्पक्षता और समान व्यवहार के मानक के संदर्भ में। यह आकस्मिकता भी उत्पन्न नहीं हुई। हिस्सेदारी केवल इसलिए अपीलकर्ता समूह के पक्ष में झुक गई क्योंकि उन्होंने अधिक शेयरों के लिए आवेदन किया था, जबकि उत्तरदाता समूह ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता समूह द्वारा अधिक शेयरों के लिए आवेदन और उत्तरदाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के विकल्प के कारण शेयरों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें शेयरों का आवंटन

व्यायाम को दोषपूर्ण, अवैध या उत्पीड़न के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

46. ऐसा कोई मामला नहीं है कि उत्तरदाताओं के लिए आवेदन करने में कोई बाधा थी, एक बार जब यह पाया जाता है कि उन्हें सूचित किया गया था और आवेदन करने के उनके अधिकार के बारे में पता था।

कुछ स्थितियों में, एक एकल कार्य में उत्पीड़न का मामला पाया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अतिरिक्त शेयरों का आवंटन किया गया हो। मौजूदा शेयरधारकों के अलावा कोई अन्य।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें हस्मुखलाल माधवपाल पटेल बनाम. एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

सभी मौजूदा शेयरधारकों पर शर्तें समान रूप से लागू की गईं। शेयरधारिता में परिवर्तन, जिसमें अपीलकर्ता की हिस्सेदारी 30.80% से बढ़कर 63.58% हो गई, उत्तरदाताओं द्वारा आवेदन करने से इनकार करने का परिणाम है। मौका दिया।

दो प्रश्न जीवित रहते हैं

47. उत्तरदाताओं की शिकायतों में से एक यह है कि अधिकृत पूंजी में वृद्धि और शेयरों के आवंटन का कथित कारण भी नए धन का निवेश करना था। हालाँकि, नए फंड केवल Rs.21 लाख तक ही आए। अपीलकर्ता समूह के सदस्य को आवंटित शेयरों के लिए प्रतिफल की शेष राशि को पहली प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा अपीलकर्ता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अधिकृत पूंजी में वृद्धि और शेयरों के आवंटन के लिए स्पष्ट कारण वास्तविकता के अभाव से भरा हुआ है और वास्तविक इरादा कंपनी में नियंत्रित ब्याज पर कब्जा करना था। अपीलकर्ताओं द्वारा यह इंगित करते हुए इसे पूरा करने की कोशिश की जाती है कि बकाया ऋण को देखते हुए, एक विषम ऋण-इक्विटी अनुपात था जो एक बाधा थी और कंपनी द्वारा अपीलकर्ता समूह से देय ऋण को बट्टे खाते में डालने का परिणाम कंपनी को एक बेहतर वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना था।

उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि ऋण भी प्रत्यर्थी के समूहों के कारण थे।

48. दूसरा विवाद जो बना हुआ है वह यह है कि 18.12.2009 पर जब निदेशक मंडल ने 10 लाख शेयर जारी करने का फैसला किया

शेयरधारकों को उन शेयरों को आवंटित करने के लिए जो अतिरिक्त शेयर लेने के इच्छुक थे, यह सब इस उम्मीद में किया गया था कि शेयरधारक अधिकृत पूंजी को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की मंजूरी देंगे। दूसरे शब्दों में, बोर्ड का अधिकार शेयरों के आगे के निर्गम पर निर्णय लेने के लिए निदेशकों पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि इसमें शेयरों की पेशकश की जा रही थी जब अधिकृत पूंजी केवल 1 करोड़ रुपये थी। गाड़ी को घोड़े के सामने नहीं रखा जा सकता था। पहला कदम शेयरधारकों की बैठक आयोजित करना होना चाहिए और शेयरधारकों को अधिकृत पूंजी में वृद्धि को मंजूरी देनी चाहिए। इसके बाद ही, दूसरे शब्दों में, निदेशक मंडल वही कर सकता था जो वह 18.12.2009 पर करना चाहता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. इस संबंध में नानालाल ज़वेर (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन प्राप्त होता है।
50. दूसरी ओर अपीलार्थियों का मामला यह है कि निदेशक मंडल की बैठक के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि

18.12.2009 पर होने वाली बैठक में, शेयरधारकों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अधिकृत पूंजी बढ़ाने के बाद ही विचार किया जाना था। 51. नानालाल ज़वेर (ऊपर) में निर्णय पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश कनिया, अपनी राय में आगे बढ़े

अपील को खारिज करने के लिए। न्यायमूर्ति एम. सी. महाजन और न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने अलग-अलग सहमति वाली राय लिखी। न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अपील को खारिज किया जाना चाहिए और वे न्यायमूर्ति एस. आर. दास के तर्क से काफी हद तक सहमत थे। विचाराधीन कंपनी में, अधिकृत पूंजी Rs.10 लाख थी। मुकदमे में वादी, जिससे मामला उत्पन्न हुआ, एक निश्चित समूह के साथ जुड़े हुए थे, जिसने कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के लिए आगे बढ़े थे। यह, जाहिरा तौर पर, समूह से 'कंपनी की रक्षा' करने के लिए था, जिसने कंपनी में नियंत्रण हित हासिल करने की मांग की थी, कि कंपनी के प्रबंधन में समूह ने अप्रकाशित अधिकृत पूंजी की शेष राशि जारी करने का फैसला किया। द.

शेयर 4 के अनुपात में जारी किए गए थे: 5 मौजूदा शेयरधारकों के लिए। यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी शेष शेयर, जिसके लिए आवेदन नहीं किया गया था, का निपटान निदेशकों द्वारा उस तरीके से किया जाना था, जिसे वे सबसे अच्छा मानते थे। न्यायमूर्ति एम. सी. महाजन द्वारा दी गई राय से हम निम्नलिखित को दो प्रश्नों में से एक पाते हैं, जो स्पष्ट किए गए थे:

" 11 (1) क्या निदेशकों द्वारा आगे शेयर जारी करना धारा 105-सी के प्रावधानों का उल्लंघन था

भारतीय कंपनी अधिनियम, '।

52. कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 105-सी निम्नानुसार है:
" 105 - सी. पूंजी का आगे का मुद्दा। जहां निदेशक आगे ASMUKHLAL MADHAVLAL PATEL v जारी करके कंपनी की पूंजी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं।

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

ऐसे शेयरों की पेशकश प्रत्येक सदस्य (चाहे वह किसी भी वर्ग का हो) द्वारा रखे गए मौजूदा शेयरों के अनुपात में सदस्यों को की जाएगी और ऐसा प्रस्ताव नोटिस द्वारा किया जाएगा जिसमें उन शेयरों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी जिनके लिए सदस्य हकदार है, और एक समय को सीमित किया जाएगा जिसके भीतर प्रस्ताव, यदि स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अस्वीकार माना जाएगा और ऐसे समय की समाप्ति के बाद, या उस सदस्य से सूचना प्राप्त होने पर जिसे ऐसी सूचना दी जाती है कि वह प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से इनकार करता है, निदेशक उसे इस तरह से निपट सकते हैं जो वे कंपनी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद समझते हैं।

60. अपीलार्थियों के मामले में, जो असफल वादी थे, धारा 105-सी का उल्लंघन किया गया था। सीई एम. सी. महाजन की राय में, हम निम्नलिखित सूत्रीकरण पाते हैं:

" 18. अनुभाग में प्रयुक्त भाषा तीन को स्वीकार करती है

संभावित व्याख्याएँ:

(1) कि इसका दायरा उन मामलों तक सीमित है जहाँ वृद्धि हुई है

धारा के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की पूंजी

50 ;

(2) कि यह धारा अपने दायरे में अतिरिक्त पूंजी के सभी निर्गम को शामिल करती है, चाहे वह नाममात्र पूंजी को बढ़ाकर या अधिकृत पूंजी के भीतर और शेयर जारी करके किया गया हो; (

3) कि यह धारा केवल उन मामलों में लागू होती है जहां निदेशक अधिकृत सीमा के भीतर और शेयर जारी करते हैं। "

61. उक्त मामले में अपीलकर्ताओं ने दूसरा बहाना पेश किया, जबकि उत्तरदाताओं (अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी) ने इसे तीसरी व्याख्या के तहत लिया। न्यायमूर्ति एम. सी. महाजन ने कहा,

इस प्रकार है:

" 23. खंड की तीसरी व्याख्या को खंड के शुरुआती भाग में विधायिका द्वारा नियोजित भाषा से समर्थन मिलता है, जिसमें कहा गया है: जहां निदेशक आगे के शेयरों को जारी करके कंपनी की पूंजी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। (जोर दिया गया) निदेशक केवल बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं

जब वे अधिकृत पूंजी से और शेयर जारी करते हैं तो अपनी पहल पर पूंजी। किसी अन्य मामले में निदेशक स्वयं किसी कंपनी की पूंजी में वृद्धि के बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं।

धारा 50 के तहत पूंजी को केवल एक संकल्प [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी से। एक बार जब कंपनी ने नाममात्र बढ़ा दिया है पूंजी, फिर निदेशक नई सीमा के भीतर शेयर जारी कर सकते हैं। इसलिए निदेशकों का अधिकार, कड़ाई से बोलते हुए, पूंजी की वृद्धि के संबंध में वृद्धि तक सीमित है

अधिकृत सीमा। वे अपने निर्णय से कंपनी की नाममात्र की पूंजी में वृद्धि नहीं कर सकते। इस भाषा को देखते हुए तीसरी

खंड की व्याख्या अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होती है।

62. न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने अपनी अलग सहमति वाली राय में कहा कि

इस बात से सहमति जताते हुए कि अपील को रद्द किया जाना चाहिए, थोड़ा अलग कारण चुनें। न्यायमूर्ति एस. आर. दास जिनके साथ न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी भी थे।

घ, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 65. पहला सवाल यह है कि क्या खंड विचार करता है।

अधिकृत सीमा से ऊपर या केवल अधिकृत सीमा से नीचे पूंजी की वृद्धि। कंपनी की ओर से पेश विद्वान अटॉर्नी जनरल आग्रह करते हैं कि "आगे के शेयर" शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए। "कंपनी की पूंजी बढ़ाने का निर्णय" शब्दों के साथ संयोजन और, इस प्रकार पढ़ें, का अर्थ उन शेयरों से होना चाहिए जो अधिकृत पूंजी से परे पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। उनका तर्क है कि इस मामले में धारा 105-सी लागू नहीं होती है।

66. धारा 50, अन्य बातों के अलावा, कंपनी के संगठन के ज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन से संबंधित है।

नए शेयर जारी करके अपनी शेयर पूंजी को बढ़ाना। नए शेयर जारी करके ज्ञापन में बदलाव का विचार ही स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह उस अधिकृत पूंजी से ऊपर शेयर पूंजी को बढ़ाने पर विचार करता है जिसके साथ कंपनी ने खुद को पंजीकृत किया था। यह वृद्धि केवल कंपनी ही कर सकती है। धारा 50 की उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार एक आम बैठक में। प्राधिकृत सीमा से ऊपर की यह वृद्धि संभवतः इसके द्वारा नहीं की जा सकती है।

निदेशक अपनी जिम्मेदारी पर। धारा 105-सी, हालांकि, आगे के शेयरों के निर्गम द्वारा पूंजी में वृद्धि की बात करती है। उपयोग किए जाने वाले शब्द पूंजी हैं और साझा पूंजी नहीं हैं और आगे के शेयर हैं और नए शेयर नहीं हैं। यह निदेशकों द्वारा वृद्धि की बात करता है। इसलिए, यह खंड केवल पूंजी की ऐसी वृद्धि पर विचार करता है जो निदेशकों की निर्णय लेने की क्षमता के भीतर हो। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस धारा का उद्देश्य एक ऐसे मामले को शामिल करना है जहां निदेशक

अधिकृत सीमा के भीतर और शेयर जारी करके पूंजी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि यह केवल उसी असमूखलाल मध्य पटेल v के भीतर है।

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

यह सीमा कि निदेशक आगे शेयर जारी करने का निर्णय ले सकते हैं, जब तक कि कंपनी। ऐसा कहा जाता है कि धारा 105-सी इसके बाद लागू होती है। कंपनी ने एक आम बैठक में इसे बदलने का फैसला किया है।

नए शेयर जारी करके अपनी शेयर पूंजी बढ़ाकर ज्ञापन।

यदि कंपनी ने एक आम बैठक में वृद्धि पर निर्णय लिया है

नए शेयरों के निर्गम द्वारा अपनी शेयर पूंजी का, तो यह पूरी तरह से है

निदेशकों द्वारा पूंजी बढ़ाने का निर्णय लेने की बात करना अनुचित है,

क्योंकि वृद्धि पहले से ही तय की जा चुकी है

बैठक में नई पूंजी जारी करके अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने का निर्णय लिया गया शेयरों, बढ़ी हुई पूंजी इसकी अधिकृत पूंजी बन जाती है और

तब यदि निदेशक धारा 105-सी के तहत वृद्धि करने का निर्णय लेते हैं

आगे के शेयरों के निर्गम द्वारा पूंजी, तो यह निर्णय कुछ भी नहीं है

नए अधिकृत निकाय के भीतर पूंजी जुटाने के निर्णय से अधिक

सीमा। अंत में, यदि धारा 105-सी को लागू किया जाना था अधिकृत सीमा से अधिक पूंजी की वृद्धि का मामला तो ऐसा है

निर्माण से अब तक कंपनियों को विसंगत परिणाम मिलेंगे जिन्होंने तालिका ए को अपनाया है, क्योंकि खंड के साथ व्यंजन नहीं है

तालिका ए का विनियम 42, जो आगे दिखाया जाएगा, लागू होता है।

अधिकृत सीमा से अधिक पूंजी की वृद्धि करना। यदि विधायिका

इसका आशय यह था कि धारा 105-सी सभी कंपनियों पर लागू होनी चाहिए अधिकृत सीमा से अधिक पूंजी की वृद्धि का मामला, फिर

सबसे सरल बात यह होती कि विनियमन 42 को अनिवार्य बना दिया जाता। विनियमन, एक धारा को लागू करने के बजाय जो अपनी शर्तों में

विनियमन 42 से अलग है और जो इसलिए स्थिति बनाता है

इस मामले के इस दृष्टिकोण में कि धारा स्पष्ट रूप से लागू होती है इस मामले के तथ्य "।

(जोर दिया गया)

63. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 में आगे के लिए प्रावधान किया गया है।

पूँजी से। धारा 81 (1) निम्नानुसार है:

" 81. पूँजी का आगे का मुद्दा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) जहाँ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय कंपनी का गठन या किसी कंपनी की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय

उस कंपनी में शेयरों के आवंटन से वर्ष

इसके गठन के बाद पहली बार, जो भी पहले हो, यह प्रस्तावित है के आवंटन द्वारा कंपनी की अभिदत्त पूँजी बढ़ाएँ

((क) ऐसे और शेयरों की पेशकश उन व्यक्तियों को की जाएगी जो प्रस्ताव की तारीख, के इक्विटी शेयरों के धारक हैं

कंपनी, अनुपात में, लगभग परिस्थितियों के रूप में स्वीकार करते हैं,

उस तारीख को उन शेयरों पर भुगतान की गई पूँजी;

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव निर्दिष्ट करते हुए सूचना द्वारा किया जाएगा -

प्रस्तावित शेयरों की संख्या और एक समय को सीमित करना जो इससे कम न हो

प्रस्ताव की तारीख से पंद्रह दिन जिसके भीतर प्रस्ताव, यदि

स्वीकार नहीं किया जाएगा, अस्वीकार किया गया माना जाएगा; (सी) जब तक कि

उसे या उनमें से किसी को दिए गए शेयरों का त्याग करने के लिए संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में; और खंड में निर्दिष्ट सूचना

((ख) इस अधिकार का एक कथन होगा;

(घ) उपरोक्त सूचना में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद,

या उस व्यक्ति से पूर्व सूचना प्राप्त होने पर जिसे ऐसा

नोटिस दिया जाता है कि वह प्रस्तावित शेयरों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है,

निदेशक मंडल उन्हें इस तरह से निपटा सकता है कि वे

कंपनी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद सोचें।

स्पष्टीकरण। - इस उप-खंड में, "इक्विटी शेयर पूँजी" और इक्विटी शेयरों का वही अर्थ है जो धारा 85 में है। ”

(जोर दिया गया)

64. धारा 81 (1ए) किसी अन्य को शेयरों की पेशकश की अनुमति देती है।

एनएस, यदि कुछ शर्तों को पूरा किया गया था। धारा 81 (2) निम्नानुसार है:

" 81 (2) उप-धारा (1) के खंड (ग) में कुछ भी नहीं माना जाएगा।

(क) उस समय को बढ़ाने के लिए जिसके भीतर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए, या

(ख) किसी भी व्यक्ति को त्याग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करना।

दूसरी बार, इस आधार पर कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्मुखलाल माधव पटेल v.

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

त्याग जो पहले किया गया था, उसने शेयर लेने से इनकार कर दिया है

त्याग में शामिल।

65. धारा 81 (3) (ए) में प्रावधान किया गया है कि धारा 81 में कुछ भी निजी कंपनी पर लागू नहीं होगा। धारा 81 के अन्य भाग हैं, जिनकी आवश्यकता है

66. धारा 81 (1) के अवलोकन से संकेत मिलता है कि इसमें कंपनी की अभिदत्त पूँजी को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। 'आगे शेयर'। कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 105-सी, जिसे हमने देखा है, में 'जहां निदेशक वृद्धि करने का निर्णय लेते हैं' शब्दों का उपयोग किया गया है।

'आगे के शेयर' जारी करके कंपनी की 'पूँजी'। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 में उपयोग किए गए शब्द हैं 'आगे के शेयरों के आवंटन द्वारा कंपनी की अभिदत्त पूँजी को बढ़ाने का प्रस्ताव है'।

67. एक कंपनी की अधिकृत पूँजी, जिसे कंपनी की नाममात्र पूँजी के रूप में भी जाना जाता है, अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करती है -

शेयर जो जारी किए जा सकते हैं। यह एसोसिएशन के ज्ञापन में इंगित किया जाना चाहिए। इसे केवल कंपनी द्वारा आम सभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में, हम नोटिस कर सकते हैं कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची I की तालिका ए का विनियम 44, जो इस प्रकार है:

" 44. कंपनी, समय-समय पर, सामान्य संकल्प द्वारा,

शेयर पूँजी को ऐसी राशि से बढ़ाएँ, जिसे ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित किया जाए, जो संकल्प में निर्दिष्ट की जाए।

68. दूसरे शब्दों में, निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत पूँजी में वृद्धि नहीं की जा सकती है। यह अधिकृत पूँजी से बाहर है कि एक कंपनी शेयर जारी करती है। इसके बाद यह जारी की गई पूँजी बन जाती है। जो भी जारी किया जाता है, उसकी सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसे भी अभिदान दिया जाता है, वह अभिदान पूँजी बन जाएगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (32) में भुगतान की गई पूँजी को भुगतान के रूप में जमा की गई पूँजी के रूप में परिभाषित किया गया है। अभिदत्त पूँजी का पूर्ण या आंशिक भुगतान किया जा सकता है।

69. हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अधिकृत पूँजी में वृद्धि बोर्ड की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 291 में विचार किया गया है। नानालाल ज़वेर (ऊपर) में, यह न्यायालय [2023] 8 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिवार्य रूप से इस प्रश्न से निपटने के लिए कि क्या शेयरों का एक और निर्गम होने पर शेयरों की पेशकश करने का दायित्व, पहले के अधिनियम की धारा 105-सी के अनुरूप किया जाना चाहिए, जो कि, जैसा कि हमने देखा है, अनिवार्य रूप से 1956 के अधिनियम की धारा 81 के तहत शासन जारी है। यह उक्त संदर्भ में है कि न्यायालय ने कहा कि निदेशक अपनी पहल पर केवल मौजूदा अधिकृत पूंजी से शेयरों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकृत पूंजी में वृद्धि केवल कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों की बैठक में की जा सकती है। यह आगे चला गया है

अभिनिर्धारित किया कि एक बार अधिकृत पूंजी बढ़ाए जाने के बाद, निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 105-सी के तहत कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

70. वास्तव में, उक्त मामले में, न्यायालय ने पाया कि 'कंपनी की पूंजी' अभिव्यक्ति एक अस्पष्ट वाक्यांश था और इसका अर्थ या तो हो सकता है

71. कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 81 के तहत स्थिति समान रही क्योंकि यह केवल कंपनी है, अपनी आम सभा की बैठक में, जो अधिकृत पूंजी को बढ़ा सकती है। यह स्थिति तब भी बनी रही कि इसे अभिदत्त पूंजी में वृद्धि कहें, यह अधिकृत पूंजी की सीमा के भीतर होना चाहिए। 72. दिनांक 18.12.2009 के प्रस्ताव के अनुसार, निदेशक मंडल ने वास्तव में अधिकृत पूंजी बढ़ाने का इरादा नहीं किया था। द.

प्रस्ताव के अंतिम पैराग्राफ की सामग्री, यह स्पष्ट करती है कि निदेशक मंडल को पता था कि शक्ति के साथ निहित है अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए शेयरधारकों का सामान्य निकाय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने आगे की पूंजी जारी करने का संकल्प लिया है, हालांकि यह कहा जा सकता है कि 1 करोड़ रुपये की सीमा के संदर्भ में 'आगे कोई पूंजी' मौजूद नहीं थी, जिसका गठन किया गया था

18.12.2009 पर अधिकृत पूंजी। 1 में शेयर आवंटित करने का संकल्प: 1 अनुपात और संकेत है कि शेयर, जो लागू नहीं होते हैं

क्योंकि, अन्य शेयरधारकों को आवंटन का विषय हो सकता है, सभी आवेदनों पर विचार किए जाने पर सक्रिय होने वाले थे। कार्यवृत्त से आगे पता चलता है कि आवेदन पर विचार एक विधिवत गठित बैठक में अधिकृत पूंजी में वृद्धि की प्रतीक्षा करने के लिए किया गया था-हसमुखलाल माधव पाल पटेल बनाम।

एम्बीका खाद्य उत्पाद पी. वी. टी. लिमिटेड। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शेयरधारकों का सामान्य निकाय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करने का उचित तरीका यह हो सकता है कि शेयरधारकों द्वारा अधिकृत पूंजी बढ़ाने का संकल्प लेने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाए। यह भी उतना ही सच है कि इस तरह का प्रस्ताव 27.01.2010 पर पारित किया गया था। सवाल यह है कि क्या निदेशक मंडल के कार्य ने इसे उत्पीड़न का कार्य होने का विरोध आकर्षित किया। हम सोचेंगे कि बोर्ड के निर्णय समग्र रूप से समझे जाने वाले 18.12.2009 पर निदेशकों का मतलब केवल यह है कि आगे की पूंजी जारी करने का प्रस्ताव अधिकृत पूंजी को विधिवत बढ़ाने के बाद ही प्रभावी होना था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा 81 के अधिदेश की अवहेलना करते हुए शेयरों को आवंटित करने का संकल्प लिया था। 1 के अनुपात में और अधिक शेयरों की पेशकश की गई है: 1 मौजूदा शेयरधारकों के लिए। उन्हें अस्वीकार करने या कम या ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रस्ताव केवल अपने समूह के निदेशकों या सदस्यों को अतिरिक्त शेयर आवंटित करने के लिए था। वहाँ एक समवर्ती है

यह पता लगाना कि पूंजी में वृद्धि के लिए जाने का निर्णय, अर्थात्, अधिकृत पूंजी, हमले के प्रति संवेदनशील नहीं थी। यह निर्णय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर आधारित था। निदेशक मंडल का पूंजी बढ़ाने का उद्देश्य निश्चित रूप से वास्तविक पाया गया है। अ.

आनुषंगिक लाभ, अर्थात् शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पूरी तरह से प्रत्यर्थी के समूहों द्वारा आवेदन करने से इनकार करने का अपरिहार्य परिणाम है। हम इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते कि अपीलकर्ताओं ने पूरे मामले को पहले से देखा और जानबूझकर योजना बनाई। यदि केवल उत्तरदाताओं ने आवेदन किया होता, तो स्थिति नहीं बनती।

73. जहाँ तक इस पहलू की बात है कि कथित उद्देश्य को नए धन के सृजन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन Rs.90 लाख के स्थान पर केवल Rs.21 लाख थे

यह तथ्य सामने लाया जाता है कि कंपनी द्वारा अपीलकर्ता समूह को देय ऋणों को रद्द करके भुगतान की गई पूंजी को स्पष्ट रूप से जमा किया गया था, इस न्यायालय को इस तथ्य की अनदेखी करने से नहीं रोकना चाहिए कि ऋण-इक्विटी अनुपात में निस्संदेह सुधार किया गया है। यह वहन किया जाना चाहिए

ध्यान रखें कि पूरा विचार कंपनी के विस्तार के लिए बैंक से धन प्राप्त करना था। उत्तरदाताओं का मामला कि उनके कारण ऋण थे, भी उनके मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह अलग होता अगर उत्तरदाताओं ने आवेदन किया होता और कंपनी को उनके द्वारा दिए गए ऋण को रद्द करके विचार के समायोजन की मांग की होती और इसे अस्वीकार कर दिया जाता।

कुल मिलाकर, तथ्यों में, अपीलकर्ताओं को दोषपूर्ण या अनुचित तरीके से कार्य करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

अतिरिक्त शीयरोँ का आवंटन विशेष रूप से जब 282 के विवाद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बढ़ाने के निर्णय की वास्तविकता के बारे में एक उत्तरदाता

अपीलार्थियों के पक्ष में अधिकृत पूंजी पाई गई है। अपीलें आंशिक रूप से अनुमति है। विवादित आदेश में शेयरों को आवंटित करने का निर्देश अलग रखा जाता है। लेखापरीक्षा करने का आदेश अबाधित रहेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित

ज्ञान

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

